अध्याय 3 : उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण- एक समीक्षा

आर्थिक सुधार की आवश्यकता

1990–91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तथा सरकार विदेशों से लिए गए उधार के पुनर्भुगतान की स्थिति में नहीं थी।

- विदेशी व्यापार खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था।
- 1988 से 1991 तक इसके बढ़ने की दर इतनी अधिक थी कि 91 तक घाटा 10,644 करोड़ हो गया।
- इसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा था।
- 1990–91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय म्रुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रुप में एक बहुत बड़ी राशि उधार ली।
- अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था जिसकी दर 12% हो गयी थी।
- मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार मूल्यों (खरीद मूल्यों) में वृद्धि हुई। परिणामस्वरुप बजट के मौद्रिकृत घाटे में वृद्धि हुई। साथ–साथ आयात मूल्य में वृद्धि हुई तथा विदेशी विनिमय दर में कमी हुई ।
- परिणामस्वरुप भारत के सामने राजकोषीय तथा व्यापार घाटे की समस्या उत्पन्न हुई।
- इसलिए भारत के सामने केवल दो ही विकल्प बचे हुए थे –

    1) निर्यात में वृद्धि के साथ–साथ विदेशी उधार लेकर विदेशी विनिमय प्रवाह में वृद्धिकर भारतीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए।
    2) राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करें तथा उद्देश्यवरक संरचनात्मक समायोजन लाया जाए।

आर्थिक सुधार की मुख्य विशेषताएँ –

अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए।

- सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण
- उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।
- उदारीकरण के अंग के रुप में लाइसेंस को खत्म करना।
- आयात और निर्यात नीति को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का तथा निर्यात जन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रुप से आसान होगा।

https://www.evidyarthi.in

- डॉलर के मूल्य के रुप में घरेलु मुद्रा का अवमूल्यन।
- देश के आर्थिक स्थिति में सुधार और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया।
- राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार।
- सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) –

आर्थिक सुधार की नए मॉडल को LPG मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीव्रतर विकासशील अर्थव्यवस्था के रुप में स्थापित करना।

1. उदारीकरण – उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक राजनैतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी से है। भारत में 24 जुलाई 1991 से वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरु हुई।
2. निजीकरण – निजीकरण से तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यवसाय एवम् सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित करने से है।
3. वैश्वीकरण – वैश्वीकरण का अर्थ सामान्यतया देश की अर्थव्यवथा का विश्व की अर्थव्यवस्था के एकीकरण से है।

   भारत में LPG नीति के कुछ मुख्य बिन्दु निम्न है –

   1) विदेशी तकनीकी समझौता
   2) एम.आर.टी.पी. एक्ट 1969
   3) विदेशी निवेश
   4) औद्योगिक लाइसेंस विनियमन
   5) निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ
   6) समुद्रपारीय व्यापार के अवसर
   7) मुद्रास्फीति नियमन
   8) कर सुधार
   9) वित्तीय क्षेत्र सुधार

https://www.evidyarthi.in

10) बैंकिंग सुधार

11) लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति ।

मूल्यांकन – उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की अवधारणा एक–दूसरे से जुड़ी हुई है और इनके अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर उपलब्ध कराता है जिससे उनके बेहतर तकनीक और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के साथ नये बाजार के द्वार खुलते हैं जबकि दूसरे समूह का मानना है कि यह विकासशील देशों के घरेूल उद्योगों को संरक्षण नहीं प्रदान करता है। भारतीय संदर्भ में देखने पर हम पाते हैं कि वैश्वीकरण ने जीवन निर्वहन सुविधाओ को बेहतर किया है तथा मनोरंजन, संचार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का विस्तार किया है।

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
i) उच्च आर्थिक समृद्धि दर	i) कृषि की प्रभावहीनता
ii) विदेशी निवेश में वृद्धि	ii) रोजगारविहीन आर्थिक समृद्धि
iii) विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि	iii) आय के वितरण में असमानता
iv) नियंत्रित मुद्रास्फीति	iv) लाभोन्मुखी समाज
v) निर्यात संरचना में परिवर्तन	v) निजीकरण पर नकारात्मक प्रभाव
vi) निर्यात की दिशा में परिवर्तन	vi) संसाधनों का अतिशय दोहन
vii) उपभोक्ता की संप्रभुता स्थापित	vii) पर्यावरणीय अपक्षय

आर्थिक सुधार – 1991

1 अंक के प्रश्न –

1. भारत के आर्थिक सुधार कब प्रारंभ किये गए ?
2. उदारीकरण से आप क्या समझते हैं ?
3. निजीकरण क्या है ?
4. भूमंडलीकरण को परिभाषित करें।

3 और 4 अंक के प्रश्न

https://www.evidyarthi.in

1. 1991 में अपनाए गए आर्थिक सुधारों की व्याख्या करें।
2. भारत के लिए आर्थिक सुधारों की क्या जरुरतें थीं?
3. आर्थिक सुधारों की प्रमुख विशेषताएँ क्या है ?
4. उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीति किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखिए।
5. उदारीकरण, निजीकरण तथा भूडंलीकरण की नीति के 3–4 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को लिखिए।

6 अंक के प्रश्न –

1. 1991 में भारत में सुधारों को क्यों प्रारम्भ किया गया ?
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद सरकारी की बदली हुई भूमिका स्पष्ट करें।
3. निम्नलिखित के सन्दर्भ में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उठाये गए कदमों की व्याख्या करें –

   अ) उदारीकरण   ब) निजीकरण   स) भूमंडलीकरण
4. उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करें।

एक अंक वाले प्रश्नों के उत्तर –

1. 1991 से
2. उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति।
3. निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक उद्यमों पर पूर्ण या आंशिक अधिकार करके उनका प्रबंध किया जाता है।
4. भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ने वाले संपक्र सूत्रों को बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है ताकि विश्व की आर्थिक व सामाजिक स्तर पर पारस्परिक निर्भरता बढ सके।

https://www.evidyarthi.in

पुनरावृत्ति
(आर्थिक सुधार 1991 से)

1. नयी आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई ? 1

संकेत – जुलाई 1991

2. विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य है ? 3

संकेत –

1. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमा शुल्क व गैर सीमा शुल्कों की कमी
2. जीवन स्तर में वृद्धि
3. व्यापार नीतियों, पर्यावरणीय नीतियों विकास की नीतियों के बीच लिंक स्थापित करना।
4. एकीकृत व टिकाऊ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का विकास व व्यापार जनित झगड़ों का निवारण।

3. आर्थिक सुधारों के पीछे किन्हीं तीन कारणों को उल्लेख कीजिए ? 6

संकेत –

1. सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन
2. भुगतान संतुलन में घाटा
3. ऋणों का अत्याधिक बोझ
4. विदेशी विनिमय कोष में गिरावट

evidyarthi
https://www.evidyarthi.in